



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ खंडपीठ

रिट - सी संख्या - 2048 वर्ष 2026

चांदनी गौतम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (राजस्व) लखनऊ, एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : रीपेंद्र गुप्ता

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 12

माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला

1. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।
2. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दाखिल एक रिट याचिका है, जिसमें याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 29.11.2025 को पारित एक आदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत अपने दावे को खारिज किए जाने से व्यथित हैं, इस दावे को इस आधार पर खारिज किया गया है कि याचिकाकर्तागण ने 180 दिनों की अवधि बीत जाने के पश्चात विलंब से अपना दावा प्रस्तुत किया था।
3. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा श्रीमती सर्वेश देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य (रिट-सी संख्या 27527 वर्ष 2023) के प्रकरण में पारित निर्णय पर विश्वास व्यक्त करते हैं।
4. उक्त निर्णय में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने प्रकरण की सुनवाई की थी और गौतम यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य (2020 (11) एडीजे 321 के निर्णय पर विचार करने के पश्चात यह दोहराया था कि उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित की गई परिसीमा अनुचित और मनमानी है, और यह अवधि 75 दिनों के बजाय तीन वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह योजना निर्धारित परिसीमा अर्थात् 75 दिनों के भीतर आवेदन न करने पर किसी भी प्रकार के परिणाम का प्रावधान नहीं करती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. हमारी राय में चूंकि उपरोक्त योजना एक लाभकारी विधि है, इसलिए दावा करने की परिसीमा उचित होनी चाहिए, और यदि याचिकाकर्तागण द्वारा उक्त दावा दाखिल करने में हुए विलम्ब हेतु कोई पर्याप्त कारण बताया जाता है, तो विधि के अनुसार उस पर विचार किया जाना आवश्यक है।

6. प्रत्यर्चीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने हमारे समक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रस्तुत किया है, जो **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम गौतम यादव और अन्य** विशेष अपील अनुज्ञा याचिका संख्या 7647 वर्ष 2021 के प्रकरण से संबंधित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अपील अनुज्ञा याचिका को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए हैं:-

“इस न्यायालय के दिनांक 02.07.2021 के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्ची संख्या 1 को 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान कर दिया है और ऐसे भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया है।

नोटिस जारी किया जाए जिसका जवाब छह सप्ताह में दिया जाना है।

यद्यपि प्रत्यर्ची संख्या 1 को नोटिस भेजा जा रहा है, फिर भी उसे उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इस बीच आक्षेपित आदेश में दिया गया यह निर्देश कि अस्वीकृति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर दाखिल किए गए सभी दावों को परिसीमा के भीतर माना जाए स्थगित रहेगा।”

7. यह ध्यान दिया जा सकता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **गौतम यादव** (उपर्युक्त) के प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा पारित संपूर्ण आदेश पर रोक नहीं लगाई है, अपितु मात्र उस निर्देश पर रोक लगाई है जिसके अनुसार अस्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर दाखिल किए गए दावों को परिसीमा के भीतर माना जाना चाहिए।

8. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गौतम यादव** (उपर्युक्त) प्रकरण में परिसीमा अवधि को तीन वर्ष तक बढ़ाने संबंधी निर्देश पर रोक लगा दी है, अतः अब प्रत्येक प्रकरण की जाँच उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर करनी होगी, और यह निर्धारित करना होगा कि उक्त दावा प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब हेतु कोई पर्याप्त कारण मौजूद था या नहीं।

9. हमारी राय में प्रतिवादी ने उक्त आवेदन को दाखिल करने में हुए विलम्ब के कारणों के संबंध में याचिकाकर्तागण के तर्कों पर विचार नहीं किया है, और मात्र इस आधार पर आदेश पारित कर दिया है कि दावा विलंब से दाखिल किया गया था।

10. तदनुसार आक्षेपित आदेश को रद्द और निरस्त किया जाता है, और प्रत्यर्थी प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्तागण को सुनवाई का अवसर प्रदान करे और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसके पश्चात आज की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर एक तर्कसंगत आदेश पारित करे।

11. उपर्युक्त निर्देशों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ) (न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला)

24 मार्च 2026

आशुतोष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।